



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 835 राँची, शुक्रवार

6 अग्रहायण, 1937 (श०)

27 नवम्बर, 2015 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ।

संकल्प

26 नवम्बर, 2015

विषय:- **GRDA** के अंतर्गत विभिन्न विभागों/संस्थाओं/कार्यालयों आदि के लिए आवश्यकतानुसार भूमि के सशुल्क/निःशुल्क हस्तांतरण हेतु स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

संख्या-4/स.भू. (**GRDA**)-42/15-5288/रा०--झारखण्ड की राजधानी राँची को सुनियोजित ढंग से स्तरीय शहर के रूप में विकसित किये जाने की अवधारणा के अनुरूप विभिन्न विभागों/संस्थाओं/कार्यालयों को मुख्यालय, राँची में लाने के लिए भूमि को व्यवस्थित ढंग से आवंटित किया जाना आवश्यक था। इसी के मद्देनजर राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के अधिसूचना ज्ञापांक-1479, दिनांक 10 अप्रैल, 2015 के द्वारा भूमि के चिन्हितीकरण एवं आवंटन हेतु कमिटी गठित की गई। गठित कमिटी के अनुशंसाओं के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक-4367, दिनांक 11 सितम्बर, 15 द्वारा भूमि आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया था।

2. सम्यक विचारोपरांत सरकार द्वारा निम्नलिखित संस्थाओं को **HEC** क्षेत्र में भूमि की सशुल्क एवं निःशुल्क हस्तांतरण करने का निर्णय लिया गया है:-

क्र.	विभाग/कार्यालय का नाम	चिन्हित स्थल	वर्तमान में प्रस्तावित रकबा (एकड़ में)	सशुल्क/निशुल्क
1	रिजर्व बैंक ऑफ़ इण्डिया	HEC	4.39	7,10,75,053.00 रु0
2	नाबार्ड	HEC	2.34	3,78,85,085.00 रु0
3	डी0वी0सी0	HEC	2.75	4,45,23,125.00 रु0
4	सी0पी0डब्लू0डी0	HEC	3.22	5,21,32,505.00 रु0
5	जनगणना कार्य निदेशालय	HEC	1.17	1,89,42,530.00 रु0
6	जी0एस0आई0 की स्थापना	HEC	2.00	3,23,80,425.00 रु0
7	आई0बी0एम0 की स्थापना	HEC	2.00	3,23,80,425.00 रु0
8	पुरातत्व सर्वेक्षण कार्यालय	HEC	1.09	1,76,47,360.00 रु0
9	केन्द्रीय औषधि जाँच प्रयोगशाला	HEC	1.04	1,68,37,810.00 रु0
10	सैनिक कल्याण बोर्ड	HEC	0.99	निःशुल्क
11	सी0बी0आई0 कार्यालय भवन	HEC	2.02	निःशुल्क
12	पासपोर्ट कार्यालय भवन	HEC	2.01	निःशुल्क
13	आई0आई0एम0 राँची।	HEC	60.04	निःशुल्क
14	JSAC	HEC	2.22	निःशुल्क
15	HUDCO	HEC	0.73	1,18,18,870.00 रु0
		कुल	88.01 एकड़	

3. विभागीय संकल्प संख्या-5162, दिनांक 12 नवंबर, 2015 द्वारा मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर GRDA के अंतर्गत विभिन्न विभागों/संस्थाओं/कार्यालयों आदि के लिए आवश्यकतानुसार भूमि के सशुल्क/निःशुल्क हस्तांतरण की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

4. उपरोक्त निर्णय में मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 24 नवम्बर, 2015 में मद संख्या-08 के रूप में घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
रेमण्ड केरकेट्टा,
सरकार के अपर सचिव।
